

रिवीजनल सिविल

D. Koshal, , न्यायमूर्ति. के समक्ष,

बदन,-याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ, ई. टी. सी.,-उत्तरदाता

सी. आर. नं. 1969 का 1

26 मई 4,1970

निकासी ब्याज (पृथक्करण) अधिनियम (1951 का एलएक्सआईवी)-धारा 9 (2) विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास अधिनियम (1954 का एक्सएलआईवी)-धारा 36-20 साल से अधिक समय पहले एक गैर-निकासी के पक्ष में एक निकासी द्वारा निष्पादित बंधक-निकासी हित को अलग करने के लिए अभिरक्षक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई-बंधक-"क्या विलुप्त माना गया है-संपत्ति-क्या 60 साल से अधिक समय के प्रवाह द्वारा संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व का दावा करने वाले बंधक द्वारा अभिरक्षक-मुकदमे में निहित है-नागरिक न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र-चाहे वर्जित हो।

अभिनिर्धारित किया गया कि कोई भी निकासी ब्याज निकासी ब्याज (पृथक्करण) अधिनियम की धारा 9 (2) के तहत सभी बाधाओं से मुक्त अभिरक्षक में निहित नहीं है, जब तक कि अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई निकासी के हित को उन व्यक्तियों से अलग करने के लिए नहीं की जाती है जो बंधक होने का दावा करते हैं। निकासी हित को अलग करने के लिए अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी से संपर्क किए बिना, अभिरक्षक के लिए यह खुला नहीं है कि वह अधिनियम की धारा 9 (2) के प्रावधानों को किसी संपत्ति पर लागू करे और स्वयं यह घोषित करे कि यह अभिरक्षक में निहित है और यह कि बंधक विलुप्त हो गया है। अधिनियम सभी संयुक्त संपत्ति से निपटने के लिए तंत्र प्रदान करता है और अभिरक्षक को संपत्ति में अपने अधिकारों के निर्धारण के लिए इसका सहारा लेना चाहिए, इससे पहले कि वह इसमें हस्तक्षेप कर सके। इसलिए सिविल न्यायालयों की अधिकारिता विस्थापित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति और पुनर्वास) अधिनियम की धारा 36 के तहत समय के प्रवाह द्वारा बंधक संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व का दावा करने वाली निकासी संपत्ति के बंधककर्ता द्वारा एक मुकदमे पर विचार करने के लिए वर्जित नहीं है, जब तक कि अभिरक्षक द्वारा पृथक्करण अधिनियम के तहत कार्रवाई नहीं की जाती है।

1919 के अधिनियम IX की धारा 44 और धारा 115 C.P.C. के तहत याचिका। श्री वी. पी. अग्रवाल, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गुड़गांव, दिनांक 29 अक्टूबर, 1968 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए, जिसमें श्री आर. पी. सिंह, उप-न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी, गुड़गांव, दिनांक 10 अप्रैल, 1968 के व्यय के साथ पुष्टि की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि वाद सिविल न्यायालय द्वारा विचारण योग्य नहीं था, उचित न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वाद को लौटा दिया।

निर्णय

D. KOSHAL, न्यायमूर्ति-(1) इस पुनरीक्षण याचिका में निर्धारण के लिए जो एकमात्र प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या सिविल न्यायालयों को पक्षकारों के बीच विवाद का निर्णय करने का अधिकार

क्षेत्र है, जो निकासी संपत्ति के अभिरक्षक, पूर्वी पंजाब, जालंदूर (प्रत्यर्थी सं. 2) "अधिग्रहित निकासी संपत्ति" होना।

(2) इस याचिका को जन्म देने वाला मुकदमा याचिकाकर्ता बददन द्वारा इन आरोपों पर दायर किया गया था। विवादित भूमि को मूल रूप से सरदार, दीनू, बुध सिंह और चोखे नाम के चार व्यक्तियों के पूर्ववर्तियों द्वारा प्रतिवादियों के दादा बिहारी के पक्ष में गिरवी रखा गया था। 5 से 8, जिन्होंने प्रतिवादी संख्या के पक्ष में उप-बंधक बनाया। 9 से 22, जिन्होंने बदले में, वादी को अपने अधिकार बेच दिए। बंधक और उप-बंधक दोनों ही उपयोगी थे और "1890 से बहुत पहले" बनाए गए थे। अपने सृजन के समय से ही वादी और उसके पूर्ववर्तियों के हित में उस भूमि का कब्जा था, जिसका वादी उक्त सृजन से 60 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद समय के प्रवाह से पूर्ण स्वामी बन गया था, क्योंकि बंधक को कभी भी भुनाया नहीं गया था। भारत संघ, निकासी संपत्ति का अभिरक्षक और तहसीलदार (बिक्री) गुड़गांव, प्रतिवादी सं। क्रमशः 1 से 3, भूमि को निकासी संपत्ति के रूप में गलत तरीके से मान रहे थे और इसे नीलामी द्वारा बेचने जा रहे थे, हालांकि इस संबंध में उनका कोई अधिकार नहीं था।

(3) उपर्युक्त परिस्थितियों में वादी द्वारा दावा की गई राहत न केवल इस आशय की घोषणा थी कि वह विवादग्रस्त भूमि का स्वामी बन गया था और मूल रूप से प्रतिवादियों में निहित बंधक के मोचन का अधिकार समाप्त हो गया था, बल्कि परिणामी राहत के रूप में एक स्थायी निषेधाज्ञा भी थी जो प्रतिवादियों को भूमि पर वादी के स्वामित्व अधिकार में हस्तक्षेप करने और उसे बेचने से रोकती थी।

(4) प्रतिवादियों द्वारा वाद का विरोध किया गया था। 1 से 3 और 9। प्रतिवादी का लिखित बयान नं. 9 में उनके अनुसार वास्तविक तथ्य क्या थे, यह बताए बिना वाद में लगाए गए आरोपों का एक साधारण खंडन किया गया था। उनके द्वारा दायर एकमात्र विशिष्ट याचिका यह थी कि सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को निकासी संपत्ति प्रशासन अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों द्वारा वर्जित किया गया था (hereinafter referred to as the Evacuee Act).

(5) सिविल न्यायालयों में अधिकारिता की कमी की याचिका को प्रतिवादी सं। 1 से 3 हालांकि इसके समर्थन में निर्भरता निर्वासित अधिनियम की धारा 46 पर नहीं बल्कि विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 की धारा 36 पर रखी गई थी (hereinafter referred to as the Compensation Act). उन्होंने आगे कहा कि विचाराधीन बंधक, 20 वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण, निकासी ब्याज (पृथक्करण) अधिनियम, 1951 (इसके बाद पृथक्करण अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 9 (2) के प्रावधानों के आधार पर विलुप्त हो गया था कि वाद में भूमि इस प्रकार निकासी संपत्ति बन गई थी और प्रतिवादी नं। 2 और यह कि अंततः यह प्रतिवादी नं। 1 क्षतिपूर्ति अधिनियम की धारा 12 के अधीन। यह दावा किया गया था कि भूमि को इस प्रकार "विस्थापित संपत्ति का अधिग्रहण" किया जा रहा है, प्रतिवादी संख्या। 1 से 3 उसी के निपटान के लिए पूरी तरह से सक्षम थे।

(6) अभिरक्षक, निकासी संपत्ति, पंजाब और अन्य बनाम जाफरान बेगम (1) पर भरोसा करते हुए नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि सिविल न्यायालयों को निकासी अधिनियम की धारा 46 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए वाद पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि यह प्रश्न उठाता है कि क्या विवादग्रस्त भूमि निकासी संपत्ति है या नहीं। इसलिए उन्होंने वादी के मुकदमे को खारिज कर दिया है जो इस न्यायालय में पुनरीक्षण में आया है।

(7) यह याचिका, मेरी राय में, सफल होनी चाहिए, क्योंकि नीचे दिए गए न्यायालयों ने मामले की वास्तविक प्रकृति को गलत समझा है। वादी विवादग्रस्त भूमि का गिरवीदार है और उसने वाद में स्वीकार

किया है कि मूल गिरवी रखने वाले निकासीकर्ता हैं। प्रतिवादियों द्वारा क्या दावा किया गया है सं। 1 से 3 पृथक्करण अधिनियम में परिभाषित उस अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर एक "समग्र संपत्ति" में निकासी हित है। यद्यपि उनके अनुसार ऐसा ब्याज पृथक्करण अधिनियम की धारा 9 (2) के प्रावधानों के अधीन स्वामित्व में आ गया है। हालाँकि, वे प्रावधान प्रतिवादी संख्या के मामले में मदद करने से बहुत दूर हैं। 1 से 3 तक, उनके खिलाफ जाएं क्योंकि कोई भी निकासी हित उन पर सभी बाधाओं से मुक्त नहीं हो सकता है, जब तक कि अलगाव अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई नहीं की जाती है ताकि निकासी के हितों को उन व्यक्तियों के हितों से अलग किया जा सके जो बंधक होने का दावा करते हैं, और जब तक ऐसी कार्रवाई सफलतापूर्वक नहीं की जाती है, प्रतिवादी नं। 2 के पास वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। यह ठीक वही है जो भंवरलाल और एक अन्य-बनाम क्षेत्रीय निपटान आयुक्त, जयपुर-सह-अभिरक्षक, निकासी संपत्ति और अन्य (2) के मामले में हुआ था, जिसके बाद महाजन, जे. ने बदन बनाम अभिरक्षक जालंदूर, आदि-(3) में कहा था, जिसमें तथ्य व्यावहारिक रूप से वही थे जिनके साथ हम यहां संबंधित हैं। वर्तमान मामले में विवाद यह नहीं है कि गिरवीदारों के अधिकार निकासी संपत्ति हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या मोचन की इच्छिटी अभी भी जीवित है और यह एक ऐसा मामला है जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा पृथक्करण अधिनियम के तहत निपटाना होगा, जिसने, यह सामान्य आधार है, इससे बिल्कुल भी निपटा नहीं है। सक्षम अधिकारी से संपर्क किए बिना, यह प्रतिवादी संख्या के लिए खुला नहीं है। 1 से 3 किसी संपत्ति पर पृथक्करण अधिनियम की धारा 9 (2) के उपबंधों को लागू करने के लिए और उन उपबंधों के कारण उन सभी में निहित होने की घोषणा करने के लिए। पृथक्करण अधिनियम सभी समग्र संपत्ति और प्रतिवादी संख्या से निपटने के लिए तंत्र प्रदान करता है। 1 से 3 को विवादग्रस्त भूमि में अपने अधिकारों के निर्धारण के लिए इसका सहारा लेना चाहिए, इससे पहले कि वे इसमें हस्तक्षेप कर सकें।

(8) श्री मलिक, प्रतिवादियों के लिए विद्वान वकील सं। 1 से 3 के पास वर्तमान मामले के तथ्यों पर भंवरलाल के मामले (2) (उपर्युक्त) में उक्ति की प्रयोज्यता के खिलाफ आग्रह करने के लिए कुछ भी नहीं था और वास्तव में, यह स्वीकार किया कि उनके मुवक्किल ने पृथक्करण अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई नहीं की है, सिविल न्यायालयों की अधिकारिता को बाधित नहीं कहा जा सकता है।

(9) उल्लिखित कारणों के लिए, मैं इस याचिका को स्वीकार करता हूं, नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णयों और फरमानों को अलग करता हूं और मामले को ट्रायल कोर्ट को कानून के अनुसार निर्णय के लिए भेजता हूं, जैसा कि भंवरलाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप्स द्वारा व्याख्या की गई है (2) (supra).

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

आदित्य सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

रेवाडी (हरियाणा)

